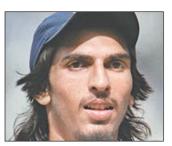
गेंदबाजों ने कराई मैच में वापसी...15



नई दिल्ली । शुक्रवार । २० दिसंबर २०१३ 314235161







सूर्योदय सूर्यास्त ०७:28

जन आंदोलनों ने लोकतंत्र में जोड़ा नया आयाम...13



न्यूज डायरी

कार हटाने को कहा तो दुकानदार को मार डाला

नई दिल्ली। तिलक नगर इलाके में दुकान के सामने से कार हटाने की बात को लेकर हुई कहासुनी में एक किराना दुकानंदार की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विस्तृत पेज उ पर ⊃

कार में स्कूटी टच होने पर एमबीए छात्र को पीटा

नई दिल्ली। हरी नगर इलाके में स्कूटी टच हो जाने से गुस्साए कार सवार युवकों ने एमबीए छात्र व उसके छोटे भाई की जमकर धुनाई कर दी। इतने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ देर बाद आधा दर्जन युवक छात्र के घर पहुंचे और परिवार के सभी सदस्यों की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी।

विस्तृत पेज उ पर ⊃

'गांधी' जाति बनाने की मांग खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंतर जातीय विवाहों से पैदा संतानों को 'गांधी' जाति के तहत रखने की मांग खारिज कर दी है। एक स्वतंत्रता सेनानी ने जनहित याचिका दायर कर यह मांग की थी। जस्टिस पी. सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई ने यह मांग रखने वाले 86 वर्षीय गांधीवादी सलेम वेलु गांधी उर्फ सी वेलु से कहा कि वह इस मामले में समाधान के लिए सरकार के पास

संजय निरुपम पर चलेगा मानहानि का मुकदमा

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम के खिलाफ मानहानि मामले में



मुकदमा चलेगा। अदालत ने बृहस्पतिवार को निरुपम के खिलाफ

आरोप तय कर दिए। भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने पिछले साल निरुपम के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। ईरानी का आरोप है कि निरुपम ने एक चैनल पर परिचर्चा के दौरान अपमानजनक व भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया।

विस्तृत पेज ६ पर ⊃

राजनयिक देवयानी बदसलूकी मामला

नाराज भारत ने अमेरिका के आगे रखी शर्त

🍑 अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। महिला राजनियक खोबरागड़े अपमानजनक गिरफ्तारी पर भारत का अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख कायम है। अमेरिका के खेद जताने को कोई भाव नहीं देते हुए भारत ने राजनियक के खिलाफ मामला बिना शर्त वापस लेने के साथ ही माफी मांगने की भी शर्त रखी है। भारत के कड़े तेवरों के बाद अमेरिका पूरे मामले को सुलझाने में जुट गया है। इस कड़ी में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने बुधवार रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन से फोन कर खेद जताया था। विवाद के जल्द निपटारे के लिए केरी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से भी बात करेंगे।

पूरे मामले में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर फिर से कहा है कि राजनियक की गिरफ्तारी के दौरान अमेरिकी प्रशासन ने शिष्टाचार को ताक पर रख दिया। इस तरह राजनियक के अपमान पर अमेरिका के खेद जता कर छुट्टी पाने की कोशिश पर भारत ने पानी

अमेरिका माफी मांगे मुकदमा वापस ले

भारत ने जॉन केरी के खेद को बताया

 सलमान खुर्शीद बोले यह देश के आत्म सम्मान का सवाल अमेरिकी राजनियकों को भारतीय एयरपोर्ट पर विशेष सुविधाएं मिलना बंद

देवयानी मामले में अमेरिका ने सकारात्मक रुख का संकेत दिया है। राजनीतिक मामलों की अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शरमन ने फोन पर विदेश सचिव सुजाता सिंह से बात की।

अमेरिका ने दिए सकारात्मक संकेत

20-25 मिनट की बातचीत में सिंह और शरमन ने मामले को निपटाने के कदमों पर चर्चा की। शरमन ने साफ किया कि प्रीत भरारा का बयान अमेरिका का रुख नहीं है।

नौकरानी के परिवार को भारत से सुरक्षित निकाला : प्रीत भरारा

भारतीय मल के अमेरिकी सरकारी वकील प्रीत भरारा ने देवयानी के खिलाफ कार्रवाई को सही करार दिया है। भरारा ने कहा कि नौकरानी संगीता रिचर्ड और उसके परिवार की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही थी। इसके लिए भारत में कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। नौकरानी को अमेरिका से भारत लौटने पर मजबूर किया जा रहा था। उसके परिवार को परेशान किया जा रहा था। ऐसे में उसके परिवार को भारत से सुरक्षित निकालना जरूरी था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद देवयानी की तलाशी तो ली गई, लेकिन उनके साथ शिष्टाचार निभाते हुए अच्छा व्यवहार किया गया। उन्हें कॉफी के लिए भी पूछा गया और फोन करने की भी इजाजत दी गई।

विदेश मंत्री के साथ-साथ संसदीय कमलनाथ ने केरी के खेद जताने कार्यमंत्री कमलनाथ ने भी को नाकाफी बताते हुए कहा कि फेर दिया है। बृहस्पतिवार को अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला। अमेरिका के माफी मांगने से ही

कि यदि उनकी बेटी

देवयानी के पिता उत्तम खोबरागडे ने कहा है के खिलाफ अमेरिका में लगाए वीजा धोखाधड़ी के झूठे आरोप वापस नहीं लिए जाते हैं तो वह अनशन पर

भारत ने कहा, अमेरिका ने भारतीय कानुनी प्रक्रिया में दखल दिया

पिता ने दी अनशन की धमकी

भरारा के बयान पर पलटवार में भारत ने उनपर देश की न्यायिक प्रक्रिया में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विएना संधि के तहत पहले तो देवयानी की गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए थी। फिर उनके साथ सामान्य शिष्टाचार तक नहीं निभाया गया। इस मामले में पीड़ित सिर्फ देवयानी हैं। भरारा के बयान से यह भी साफ है कि अमेरिका को भारत में नौकरानी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चलने की जानकारी थी। ऐसे में नौकरानी के परिवार को अमेरिका ले जाने की क्या जरूरत पड गई। भारत ने सवाल उढाया है कि क्या किसी विदेशी सरकार को भारतीय नागरिकों को भारत से बाहर निकालने का हक है, जबिक उस पर यहां कोर्ट में मामले चल रहे हों।

> शेष पेज ९ पर ⊃ संबंधित खबरें पेज उ और 13 पर ⊃

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने लवली

अमर उजाला ब्यूरो

नर्ड दिल्ली। जयप्रकाश अग्रवाल ने जिस दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसी दिन से यह हवा चल रही थी कि शीला दीक्षित को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। लवली पहले सिख नेता हैं, जिन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का मुखिया बनाया गया है। अरविंदर महज 45 साल के हैं और चार बार से विधायक हैं। शीला सरकार में मंत्री भी थे। वह दिल्ली प्रदेश के 21वें अध्यक्ष बने हैं।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस विरोधी हवा में चौथी बार जीत कर आने का लाभ उन्हें मिला है। इतना ही नहीं वह युवा होने के साथ-साथ तेज-तर्रार नेता भी हैं। उनको कमान सौंप कर कांग्रेस 1984 के दंगे के दाग से छूटे सिख मतदाताओं को मैसेज देना चाहती है। विधायक हारून यूसुफ को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाए जाने की चर्चा है। खास



घोषणा पत्र की शर्त पर 'आप' को समर्थन

नई दिल्ली (ब्यूरो)। अरविंदर सिंह लवली ने साफ किया है कि आम आदमी पार्टी (आप) को बिना शर्त नहीं बल्कि घोषणा पत्र लागू करने की शर्त पर समर्थन दिया गया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने 'आप' को नहीं बल्कि उसके घोषणा पत्र को समर्थन दिया है। बार-बार मीडिया में आ रहा है कि हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। ऐसा नहीं है शर्त घोषणा पत्र को लागू करने की है क्योंकि पार्टी ने जनता को घोषणाओं का भ्रम दिखाकर वोट लिया है। अब सरकार बनाने से भाग रही है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन आप ने झूठे वादों से सत्ता छीनी है।

बात यह है कि अरविंदर और यूसुफ दोनों ही शीला दीक्षित के करीबी हैं।

हालांकि वरिष्ठ नेताओं की भरमार वाली पार्टी में सबको साथ लेकर चलना लवली के लिए आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की आंधी में 43 सीट से घटकर आठ सीट पर सिमटने वाली कांग्रेस को आगामी

लोकसभा चुनाव में खड़ा करने की चुनौती भी नए प्रदेश अध्यक्ष को झेलनी होगी। वैसे लवली को छात्र राजनीति, युवक कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव है। पहली बार 1998 में 73 फीसदी मतों के साथ विधायक बने और दूसरी बार विधायक बनने पर मंत्री बनाया संबंधित खबरें पेज 2 ⊃

जाट आरक्षण की ओर बढ़े सरकार के कदम

यूपीए सरकार ने चला चुनावी दांव, एनसीबीसी से राज्यों की राय के मृताबिक मांगी सिफारिश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आम चुनाव का बिगुल बजने के ठीक पहले युपीए सरकार जाट आरक्षण का बड़ा राजनीतिक दांव चलने की तैयारी में है। सरकार ने बृहस्पतिवार को

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) से जाट समदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राज्यों की राय के आधार पर सिफारिश मांगी है। कैबिनेट ने कहा है कि इस संबंध में सर्वे की प्रक्रिया से इतर एनसीबीसी राज्यों की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर अपनी सिफारिश भेजे। चूंकि नौ राज्यों में जाट समुदाय को पहले ही ओबीसी का दर्जा हासिल है, इसलिए सिफारिश मांगे जाने को महज औपचारिकता ही माना जा रहा है। एक पखवाडे के अंदर

एनसीबीसी इस संबंध में सिफारिश भेज देगा। इस संबंध में गठित मंत्री समूह ने जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में रखने की पहले ही सिफारिश की थी। जाट समुदाय की दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में बड़ी आबादी है, जो लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। शेष पेज 9 ⊃

जनवरी अंत तक हो सकती है घोषणा सत्रों का कहना है कि जाटों को आरक्षण के

संबंध में एनसीबीसी से सिफारिश मांगना महज औपचारिकता है। चूंकि सरकार ने राज्यों से उपलब्ध दस्तावेज और राय के अनुरूप एनसीबीसी से

सिफारिश मांगी है,

सिफारिश आरक्षण

के खिलाफ आने

की गुंजाइश नहीं

है। मॉना जा रहा

है कि एनसीबीसी

अधिकतम तीन

सप्ताह में अपनी

सिफारिश केंद्र

सरकार को भेज

देगा। इसके बाद

सरकार जनवरी

महीने के अंत तक

जाटों को ओबीसी

में शामिल करने

की घोषणा कर

इसलिए उसका



नौ राज्यों में तस्वीर बदल सकते हैं जाट

जाटों की मौजदगी 16 राज्यों में हैं। मगर इनकी मुख्य उपस्थिति हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी में है। इन राज्यों में जाट सियासी तस्वीर बदलने की कूव्वत रखते हैं। इसी कारण सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का सियासी पासा फेंका है।

सुनील जेम्स को मिली टोगो की जेल से मुक्ति समुद्री लुटेरों से संबंध रखने के आरोप में थे छह महीनों से बंद, दूसरे कैप्टन विजयन भी रिहा

और बहन ने बीते दिनों प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। आखिरकार भारतीय नाविक सुनील जेम्स को छह महीने के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो की जेल से मुक्ति मिल ही गई। भारत की ओर से लगातार डाले जा रहे दबाव के बाद टोगो ने समुद्री लुटेरों से मिले होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेम्स को रिहा कर दिया। जेम्स के साथ ही इस मामले में बंद दूसरे कैप्टन विजयन को भी रिहा कर दिया गया है।



अपने मासूम बेटे के शव का कर सकेंगे अंतिम संस्कार

भारतीय नाविक सुनील जेम्स की रिहाई की खबर से परिजनों ने ली राहत की सांस।

उल्लेखनीय है कि जेम्स के जेल में रहने जेम्स का परिवार उनके आने तक बेटे के दौरान ही पिछले दिनों उनके 11 माह के बेटे की मुंबई में मौत हो गई थी। था। इस सिलसिले में जेम्स की पत्नी

के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं

अकबरुद्दीन ने जेम्स और विजयन की रिहाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टोगो सरकार ने दोनों को रिहा करने का फैसला किया। इन्हें बीते 16 जुलाई को टोगो पुलिस ने समुद्री लुटेरों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार कर

मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद

लिया था। जबकि भारत का कहना था कि इन्होंने ही टोगो प्रशासन को समुद्री लुटेरों के बारे में जानकारी दी थी।

इरोम शर्मिला के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी

दिल्ली अनशन के दौरान आत्महत्या के प्रयास का है आरोप

नई दिल्ली (ब्यूरो)। अदालत ने मणिपुर अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा में विवादास्पद संशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम के विरोध में 13 वर्ष से भुख हड़ताल पर बैठीं सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को 30 जनवरी को पेश करने के लिए प्रोडक्शन

वारंट जारी किया है। उन पर भूख हड़ताल के जरिए आत्महत्या के प्रयास का मामला विचाराधीन है। मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन

आकाश जैन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शर्मिला को पेश होने के लिए 30 अक्तूबर को निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद वे पेश नहीं हुईं। इसलिए प्रोडक्शन वारंट जारी करना जरूरी है।

शर्मिला की खराब हालत का तर्क रखने पर स्पष्ट किया कि यदि वे असमर्थ हैं तो जबरन पेश न किया जाए। शर्मिला के पेश न होने की स्थिति में बचाव

पक्ष पेशी से छूट के लिए आवेदन दायर कर सकता है। साथ ही अदालत ने अभियोजन पक्ष को मामले में गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 30 जनवरी तय कर दी है। शर्मिला ने मणिपुर में लागू विवादास्पद कानून के विरोध में 6 से 8

अक्तूबर 2006 के दौरान भूख हड़ताल शुरू की थी और पुलिस ने आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था।

दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री राजमार्ग को हरी झंडी

7 स्टेट हाइवे को केंद्र सरकार की फंडिंग का रास्ता खुला

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश के राजमार्गों के कायाकल्प की उम्मीद जगी है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर खास मेहरबानी दिखाते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक झटके में 7 स्टेट हाइवे को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी है। निजी भागीदारी के जरिए निर्माण पूरा करने के लिए दो से ढाई साल का समय दिया गया है। केंद्र ने यूपी के हाइवे को मंजूरी देने में जो तेजी दिखाई है, उसे यूपीए के सहयोगी दलों पर मेहरबानी के तौर पर देखा जा रहा है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन स्टेट हाइवे को मंजूरी दी गई है, उनमें दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री, बरेली-अल्मोड़ा और वाराणसी-शक्तिनगर के बीच बन रहे 4 लेन हाइवे शामिल हैं। इनके मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर-हरदोई-लखनऊ, अलीगढ़-मथुरा और ताड़ीघाट-बरा के बीच 4 लेन हाइवे को भी केंद्र की हरी झंडी मिल गई है। निजी भागीदारी के जरिए बनने वाली इन सड़कों

निजी भागीदारी के तहत दो से ढाई साल में पुरा होगा काम

करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट मंजूर



यूपी-उत्तराखंड का संपर्क सुधरेगा

स इक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यूपी की जिन 7 हाइवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, उनमें 2 उत्तराखंड से जुड़े हैं। दिल्ली सहारनपुर-यमुनोत्री को जोड़ने वाले स्टेट हाइवे नंबर-57 और बरेली-अल्मोड़ा के बीच स्टेट हाइवे नंबर-37 के 4 लेन होने से दोनों राज्यों के बीच संपर्क बेहतर हो सकेगा। इसका फायदा दिल्ली और आगरा से उत्तराखंड जाने वाले पर्यटकों को मिल सकता है।

के निर्माण के एवज में 25 साल तक टोल वसूली की छूट दी

आरबीआई की ओर से ब्याज दरें नहीं बढ़ाने के बाद अब बैंकों ने दिया होम लोन ग्राहकों को सस्ते ब्याज का सरप्राइज

एसबीआई और एचडीएफसी से होम लोन लेना हुआ सस्ता

🍑 अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। मौद्रिक नीति में आरबीआई की ओर से ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिए जाने के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी फाइनेंस कंपनी ने अपने होम लोन ग्राहकों को सरप्राइज दिया है। बृहस्पतिवार को स्टेट बैंक ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में 0.15 से लेकर 0.20 फीसदी तक की कमी कर दी। यही नहीं, बैंक ने महिलाओं को ब्याज दरों में 0.05 फीसदी की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा

इसी तरह एचडीएफसी ने 75



हैं। एसबीआई और एचडीएफसी

0.15-0.25 फीसदी तक कम हुईं

होम लोन की दरें

0.05% की ब्याज में अतिरिक्त छूट किस बैंक के होमलोन की कितनी ब्याज दर (फीसदी में) एसबीआई 10.15-10.30

10.25-10.50 एचडीएफसी आईसीआईसीआई 10.10-11.25

20 दिसंबर से लागू होंगी एसबीआई और एचंडीएफसी की नई ब्याज दरें

ब्याज दरें 10.25 फीसदी कर दी के वर्ग में भी बदलाव किया है। अभी तक बैंक 30 लाख रुपये पर फीसदी की अतिरिक्त छूट के तहत बैंक अब 75 लाख रुपये तक के 10.30 फीसदी और उससे की नई दरें 20 दिसंबर से लागू होम लोन पर 10.15 फीसदी और ज्यादा के कर्ज पर 10.50 फीसदी और 75 लाख रुपये से होंगी। एसबीआई ने ब्याज दरों में 75 लाख रुपये से ज्यादा के कर्ज फीसदी ब्याज ले रहा था। ज्यादा की राशि पर 10.25 फीसदी कमी करने के अलावा होम लोन पर 10.30 फीसदी ब्याज लेगा। महिलाओं को होम लोन पर 0.05

75 लाख रुपये पर उन्हें 10.10

एचडीएफसी ने भी होमलोन के लिए बनाए नए वर्ग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(एसबीआई) की तरह हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) ने भी होम लोन के लिए नए वर्ग बना दिए हैं। कंपनी अब 75 लाख रुपये तक 10.25 फीसदी ब्याज लेगी। अभी तक 30 लाख रुपये तक के कर्ज पर कंपनी 10.50 फीसदी ब्याज ले रही थी। ब्याज दरों में छूट की सुविधा 20 दिसंबर 2013 से 31 जनवरी 2014 तक के आवेदन पर ही नए ग्राहकों को मिलेगी।